

नागरिक विविध

हरबंस सिंह, सी.जे. और बाल राज तुली से पहले, जे.

रोशन लाल कुठियाला, -याचिकाकर्ता,

बनाम

आयकर आयुक्त, नई दिल्ली, - प्रतिवादी

1972 का आयकर संदर्भ संख्या 19।

28 मार्च 1973.

आयकर अधिनियम (1939 के अधिनियम 7 द्वारा संशोधित 1922 का XI) - धारा 22 और 28 - मूल्यांकन योग्य आय वाले व्यक्ति धारा 22(1) के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं - क्या जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं - सरकार द्वारा सदन के पटल पर इस तरह का जुर्माना न लगाने का आश्वासन - निर्धारिती - क्या दंड से बचा जा सकता है - कानून की व्याख्या - कानून के एक खंड की भाषा स्पष्ट - उस समय विधानमंडल के पटल पर दिया गया आश्वासन इसके अधिनियमन की-क्या इसकी व्याख्या के लिए विचार किया जा सकता है।

माना गया कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22(1) और 28 को संयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मूल्यांकन योग्य आय है, उसे धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस में बताई गई अवधि के भीतर अपनी आय का रिटर्न दाखिल करना होगा और, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना भरना होगा। धारा 28 के तहत जुर्माना। आयकर अधिकारी धारा 22 की उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक निर्धारिती को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें निर्धारिती को कम से कम तीस दिनों की अवधि के भीतर आय का बीआईएस रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि निर्धारिती, जिसे नोटिस जारी किया गया है, निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो वह धारा 28 के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयकर अधिकारी के लिए प्रत्येक निर्धारिती को नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है। अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए। सरकार द्वारा विधानमंडल

के पटल पर दिया गया कोई भी आश्वासन कि निर्धारिती को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने की प्रथा जारी रखी जाएगी और यदि कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सार्वजनिक नोटिस में निर्धारित समय के भीतर एक निर्धारिती द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था, रिटर्न दाखिल करने में चूक के परिणामस्वरूप दंड से बचने के लिए निर्धारिती लाभ नहीं उठा सकता है।

यह माना गया कि किसी कानून के अधिनियमित होने के समय विधानमंडल के पटल पर दिए गए आश्वासन पर किसी भी न्यायालय द्वारा उस कानून के एक खंड की व्याख्या के लिए विचार नहीं किया जा सकता है यदि अनुभाग में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। अनुभाग में प्रयुक्त भाषा की व्याख्या विधानमंडल में इसके पारित होने के दौरान कही गई किसी भी बात की सहायता के बिना की जानी चाहिए। इसलिए कथित आश्वासन भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 के पारित होने के समय विधानमंडल के पटल पर दिया गया था, जिसके तहत आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 और 28 में संशोधन किया गया था कि अभ्यास अधिनियम की धारा 22(2) के तहत निर्धारितियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी करना जारी रहेगा और यदि किसी निर्धारिती द्वारा उप-धारा (1) के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस में निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। धारा 22, निर्धारित अवधि के भीतर रिटर्न दाखिल करने में चूक पर परिणामी जुर्माने से बचने के लिए निर्धारिती का लाभ नहीं उठा सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच द्वारा, अपने आदेश दिनांक 24 मई, 1972 के तहत, कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर इस माननीय न्यायालय की राय के लिए संदर्भ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 12 अगस्त, 1970 से उत्पन्न आई.टी.ए. निर्धारण वर्ष 1958-59 के लिए 1967-68 का क्रमांक 19571: “

(1) क्या, तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल ने 1922 के अधिनियम की धारा 28 के अधिनियमन के समय सदन के पटल पर दिए गए आश्वासनों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है?

(2) क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल द्वारा यह सही माना गया है कि अधिनियम की धारा 274 और 275 के साथ पठित धारा 271 (1) (ए) के तहत कार्यवाही की उचित शुरुआत हुई थी 1961 का।”

याचिकाकर्ताओं के वकील एम. एम. पुंछी।

प्रतिवादियों की ओर से डी.एन.अवस्थी और अधिवक्ता बी.एस.गुप्ता।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया: - तुली, जे. - आयकर अधिकारी ने 14 नवंबर, 1961 को भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 के तहत एक नोटिस जारी किया, जो निर्धारिती, श्री रोशन को दिया गया था। लाल कुठियाला, 30 नवंबर, 1961 को मूल्यांकन वर्ष 1958-59 के लिए।

करदाता ने आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 फरवरी, 1962 तक का समय मांगा, लेकिन वास्तव में उसने 7 मई, 1962 को रिटर्न दाखिल किया, जिसमें 3,38,591 रुपये की आय दिखाई गई। 23 मई, 1962 को अनंतिम मूल्यांकन किया गया और 2,27,307.84 पैसे का कर मांगा गया, जिसका भुगतान समय पर किया गया। की आय पर नियमित मूल्यांकन किया गया। 31 दिसम्बर 1962 के आदेश द्वारा 3,44,668 रुपये तथा कर निर्धारण 2,66,794 रुपये था। निर्धारिती को 2,25,337 रुपये का क्रेडिट दिया गया था, कुछ मामूली समायोजन के बाद अनंतिम मूल्यांकन के तहत भुगतान की गई राशि और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस 41,456 रुपये के लिए जारी किया गया था। इस राशि का भुगतान कर दिया गया।

(2) मूल्यांकन पूरा करते समय, आयकर अधिकारी ने निम्नलिखित निर्देश दिए: -

“धारा 22(1) के तहत नोटिस के डिफॉल्ट के लिए धारा 28(1) के तहत नोटिस भी जारी करें। दंडात्मक ब्याज वसूलें और धारा 18-ए के डिफॉल्ट के लिए और धारा 18-ए (3) के डिफॉल्ट के लिए धारा 18-ए (एल)/28 के तहत नोटिस भी जारी करें क्योंकि निर्धारिती ने स्वयं 3,38,591 रुपये की आय दिखाते हुए रिटर्न दाखिल किया है।”

हालाँकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील की सुनवाई होने तक निर्धारिती को धारा 28(3) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। 27 मई 1963 को धारा 271(एल)(ए) के तहत नोटिस जारी किया गया और उसी दिन निर्धारिती को भेज दिया गया। रुपये का जुर्माना 1,27,643 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील 15 नवंबर, 1967 को खारिज कर दी गई और आयकर अधिकारी ने 1,27,643 रुपये यानी कर का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाने का आदेश दिया। जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 271(1) के खंड (i) में निर्धारित है। 1961, को बरकरार रखा गया। निर्धारिती ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक और अपील दायर की और अनुरोध किया कि चूंकि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22(2) के तहत उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालाँकि वह पूर्व निर्धारिती था, उसकी आय का रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था। उनके विद्वान वकील ने त्रि- को संबोधित किया निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा:-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 274 और 275 के अर्थ में धारा 271(एल)(ए) के तहत कार्यवाही की कोई उचित शुरुआत नहीं हुई थी;

(ii) देय कर, यदि कोई हो, को गलत तरीके से निर्धारित सकल कर के रूप में व्याख्या किया गया है, जबकि धारा 156 के तहत मांग नोटिस के अनुसार देय कर 41,456.67 रुपये था और इसलिए, जुर्माना देय कर से अनुपातहीन है। ;

(iii) धारा 34 के तहत कार्यवाही में, धारा 22(1) के तहत किए गए डिफॉल्ट, यदि कोई हो, का कोई नोटिस नहीं लिया जा सकता है;

(iv) धारा 22(1) के प्रावधानों को कानून की किताब में लाने के समय सदन में दिए गए आश्वासनों के आधार पर, धारा 22(1) के तहत डिफॉल्ट के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है;

(v) जुर्माने की दर, यानी 2 प्रतिशत का मतलब अधिक गणितीय गणना नहीं है, बल्कि इसका मतलब 0 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक जुर्माना भी हो सकता है;

(vi) जिस हद तक पुराने अधिनियम के तहत कोई चूक हुई थी, पुराने अधिनियम के मूल प्रावधान लागू होते हैं और उस सीमा तक, जुर्माने की मात्रा पुराने अधिनियम द्वारा शासित होती है; और

(vii) निर्धारित धारा 271(1)(ए) के अर्थ के अंतर्गत उचित कारण के बिना नहीं था।

इन बिंदुओं पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष थे: -

(i) कि नोटिस जारी करना और उसकी सेवा उचित है, लेकिन विलंबित नोटिस जारी करने की प्रथा, जैसा कि मौजूदा मामले में है, एक ऐसी प्रथा है जो राजस्व के लिए हानिकारक साबित हो सकती है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए - बल्कि किया जाना चाहिए तुरंत रुक गया;

(ii) जुर्माना मांग नोटिस में दर्शाए गए देय कर के आधार पर लगाया जाना चाहिए, यानी 41,456 रुपये;

(iii) कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक डिफॉल्ट जारी रहता है और धारा 34 के तहत नोटिस जारी करने से धारा 22(1) के तहत किए गए डिफॉल्ट को स्वचालित रूप से माफ नहीं किया जाता है;

(iv) कि न्यायालय सदन में दिए गए आश्वासनों पर ध्यान नहीं दे सकता,

(v) जुर्माने की दर विशेष रूप से 2 प्रतिशत निर्धारित है - न अधिक न कम;

(vi) कि पुराने अधिनियम के तहत की गई चूक के लिए, पुराने अधिनियम के मूल प्रावधान लागू होंगे लेकिन दंड की कार्यवाही नए अधिनियम के तहत की जा सकती है;

(vii) कि निर्धारिती 15 फरवरी 1962 को समाप्त होने वाली अवधि तक रिटर्न दाखिल करने के लिए उचित कारण के बिना नहीं था, और निर्धारिती 15 फरवरी 1962 से 7 मई 1962 तक की अवधि के लिए उचित कारण के बिना था; और

(viii) डिफॉल्ट के लिए जुर्माने की पुनर्गणना की जानी चाहिए जैसा कि मांग के नोटिस में मांगे गए देय कर के आधार पर निर्धारित किया गया है, यानी 41,456 रुपये।

इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती को पर्याप्त राहत दी लेकिन असंतुष्ट महसूस करते हुए, निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत संदर्भ मांगा। ट्रिब्यूनल ने इस न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित दो प्रश्नों को संदर्भित किया है: -

“1. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने 1922 के अधिनियम की धारा 28 के अधिनियमन के समय सदन के पटल पर दिए गए आश्वासनों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है?

2. क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल द्वारा यह सही माना गया है कि अधिनियम की धारा 274 और 275 के साथ पठित धारा 271(एल)(ए) के तहत कार्यवाही की उचित शुरुआत हुई थी। 1961।”

1 दिसंबर, 1972 को निर्धारिती की मृत्यु हो गई और राजिंदर लाई कुठियाला (पुत्र), रविंदर लाई कुठियाला, (पुत्र) और श्रीमती की मृत्यु हो गई। लीला देवी (विधवा) को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है।

(3) संदर्भ की सुनवाई में, निर्धारिती के वकील ने प्रश्न संख्या 2 नहीं दबाया है और इसलिए, प्रश्न अनुत्तरित लौटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी कानून के अधिनियमित होने के समय सदन के पटल पर दिए गए किसी भी आश्वासन पर किसी भी न्यायालय द्वारा उस कानून के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए विचार नहीं किया जा सकता है यदि अनुभाग में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। इस्तेमाल की गई भाषा की व्याख्या विधानमंडल में इसके पारित होने के दौरान कही गई किसी भी बात की सहायता के बिना की जानी चाहिए। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22(2), जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित है, इस प्रकार पढ़ें:—

“कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, जिसकी कुल आय, आयकर अधिकारी की राय में, इतनी राशि है कि ऐसे व्यक्ति को आयकर के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है, आयकर अधिकारी उसे एक नोटिस देगा उसे

ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, तीस दिनों से कम नहीं, निर्धारित फॉर्म में एक रिटर्न

प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाता है (ऐसे अन्य विवरणों के साथ जो इसमें प्रदान किए जा सकते हैं) नोटिस) पिछले वर्ष के दौरान उसकी कुल आय।

इस प्रावधान के तहत, किसी भी व्यक्ति को आयकर अधिकारी से नोटिस मिलने तक अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। इस धारा को भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 (1939 का 7) की धारा 24 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप धारा 22 की उपधारा (1) और (2) इस प्रकार पढ़ी गईं: -

"(1) आयकर अधिकारी, प्रत्येक वर्ष मई के 1 दिन या उससे पहले, प्रेस में प्रकाशन द्वारा और निर्धारित तरीके से प्रकाशन द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसकी कुल आय पिछले वर्ष के दौरान अधिक हो गई है अधिकतम राशि जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, ऐसी अवधि के भीतर जो साठ दिनों से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि नोटिस में निर्दिष्ट की जा सकती है, एक रिटर्न, निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जा सकता है, आगे निर्धारित करते हुए (साथ में) ऐसे अन्य विवरण जो नोटिस के लिए आवश्यक हो सकते हैं) उस वर्ष के दौरान उसकी कुल आय और कुल विश्व आय: बशर्ते कि आयकर अधिकारी अपने विवेक से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के मामले में रिटर्न की डिलीवरी की तारीख बढ़ा सकता है।

2. किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसकी कुल आय, आयकर अधिकारी की राय में, इतनी राशि है कि ऐसे व्यक्ति को आयकर के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है, आयकर अधिकारी उसे एक नोटिस भेज सकता है, जिसमें उससे यह कहा जा सकता है कि सुसज्जित करना; ऐसी अवधि के भीतर तीस दिन से कम नहीं होनी चाहिए; जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है, निर्धारित प्रपत्र में एक रिटर्न और पिछले वर्ष के दौरान उसकी कुल आय और कुल विश्व आय को निर्धारित करते हुए (ऐसे अन्य विवरणों के साथ जो नोटिस में प्रदान किया जा सकता है) निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया है:

बशर्ते कि आयकर अधिकारी अपने विवेक से रिटर्न की डिलीवरी की तारीख बढ़ा सकता है।

उसी संशोधन अधिनियम द्वारा, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 28 में संशोधन किया गया, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए: -

"28(1) यदि आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त या अपीलीय न्यायाधिकरण, इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान संतुष्ट है कि कोई भी व्यक्ति: -

(ए) बिना उचित कारण के अपनी कुल आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिसे उसे धारा 22 या धारा 34 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत दिए गए नोटिस द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी या उचित कारण के बिना विफल रहा है इसे अनुमत समय के भीतर और ऐसे नोटिस द्वारा अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करना, या

(बी) * * * * *

(सी) * * * * *

वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति खंड (ए) में निर्दिष्ट मामले में दंड के माध्यम से, उसके द्वारा देय आयकर और सुपर-टैक्स की राशि, यदि कोई हो, के अलावा, एक राशि का भुगतान करेगा। उस राशि से डेढ़ गुना से अधिक, और संदर्भित मामलों में * * * * *।

(4) संशोधित धारा 22(1) और 28 की संयुक्त रीडिंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी मूल्यांकन योग्य आय थी, को उप-के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस में बताई गई अवधि के भीतर अपनी आय का रिटर्न दाखिल करना था। धारा 22 की धारा (1) और, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 28 के तहत जुर्माना लगाया जाता है। धारा 22 की उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक निर्धारिती को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने के लिए आयकर अधिकारी के पास खुला था। निर्धारिती को कम से कम तीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है और यदि निर्धारिती, जिसे नोटिस जारी किया गया था, ने निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो वह धारा 28 के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी था। यह है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयकर अधिकारी के लिए प्रत्येक निर्धारिती को उसकी आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं था। धारा 22 की उप-धारा (1) ने एक निर्धारिती पर सार्वजनिक नोटिस में बताई गई अवधि के भीतर, यदि मूल्यांकन योग्य हो, अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने का कर्तव्य लगाया, जो साठ दिनों से कम नहीं होनी थी। चूंकि इस मामले में करदाता ने निर्धारण वर्ष 1958-59 के लिए सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया, उसने अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने में चूक की और भारतीय धारा की धारा 28 के तहत जुर्माना लगाया। आयकर अधिनियम, 1922.

उस अधिनियम की धारा 34 के तहत उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जो 30 नवंबर 1961 को उन्हें दिया गया था, और उन्होंने 15 मार्च 1962 तक अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें 15 मार्च 1962 तक विस्तार की अनुमति दी गई थी। 15 फरवरी, 1962. यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें दिया गया ढाई महीने का समय अपर्याप्त था. किसी भी मामले में, उन्होंने कभी भी समय के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया और 7 मई, 1962 को अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया। ट्रिब्यूनल ने माना है कि निर्धारिती 15 फरवरी तक अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा है।, 1962, उचित कारण के बिना नहीं था और इसलिए, उस तारीख तक रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने पाया है कि 15 फरवरी, 1962 से 7 मई, 1962 तक रिटर्न दाखिल करने में चूक बिना उचित कारण के थी। उस अवधि के लिए, सदन के पटल पर दिया गया कथित आश्वासन कि करदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने की प्रथा जारी रखी जाएगी और यदि किसी करदाता द्वारा सार्वजनिक नोटिस में निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस मामले में 15 फरवरी, 1962 और 7 मई, 1962 के बीच रिटर्न दाखिल करने में चूक के परिणामस्वरूप होने वाले जुर्माने से बचने के लिए निर्धारिती का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। रिटर्न दाखिल करने के लिए धारा 34 के तहत करदाता को नोटिस जारी किया गया था और उसे 30 नवंबर 1961 को भेजा गया था, जिसके अनुसरण में उसने अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 मार्च 1962 तक का समय मांगा था। उन्हें 15 फरवरी, 1962 तक का समय दिया गया था और उन्होंने कभी भी समय बढ़ाने की मांग नहीं की। उक्त नोटिस द्वारा, यह उनके प्रासंगिक नोटिस में लाया गया कि उन्होंने सार्वजनिक नोटिस में बताए गए समय के भीतर अपनी आय का रिटर्न दाखिल नहीं करने की धारा 22(1) के तहत चूक की है और उस नोटिस की प्राप्ति पर उन्होंने विस्तार के लिए आवेदन किया था। समय की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्होंने विस्तारित समय के भीतर अपनी आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया। इन परिस्थितियों में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम की धारा 22 और 28 में संशोधन के समय सदन के पटल पर दिए गए आश्वासन पर ध्यान देने से इनकार करना पूरी तरह से उचित था। 1939, 15 फरवरी और 7 मई, 1962 की अवधि के लिए। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 पर हमारा उत्तर सकारात्मक है। निर्धारिती प्रतिवादी को इस संदर्भ की लागत का भुगतान करेगा, जिसका मूल्यांकन 250 रुपये है।

बी.एस.जी.

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए एहताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावली के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा